



इन ऑफबीट डेस्टिनेशन पर बिता सकते हैं सुकून के पल, भागदौड़ से बचने के लिए करें प्लान

TRAVELLING

घूमना-फिरना सभी को खूब अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग रोजाना की भागदौड़ से दूर ऐसी जगह पर समय बिताना चाहते हैं जहां शांति से कुछ समय रह सकें। ऐसे में हम आपको कुछ ऑफबीट डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे हैं, जहां आप सुकून के पल बिता...

• जालंधर ब्रीज. फीचर

1) जीरो, अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जीरो सुंदरता से भरपूर है। भीड़-भाड़ से दूर जीरो भारत के खूबसूरत ऑफबीट डेस्टिनेशन में से एक है। इस जगह को चावल के खेतों और देवदार की पहाड़ियों के लिए जानी जाती है। सितंबर से नवंबर और मार्च से मई तक ये जगह घूमने के लिए बेस्ट है।

2) गोकर्ण, कर्नाटक

कई खूबसूरत समुद्री शहरों में से गोकर्ण भारत की अच्छी जगहों में से एक है। अपने प्राचीन अछूते समुद्र किनारों के लिए फेमस गोकर्ण

खासतौर से एक मंदिरों वाला शहर है, जिसका वातावरण काफी आरामदायक है। भीड़-भाड़ से दूर कर्नाटक की इस जगह पर सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का मजा लें। समुद्र किनारे पर बनी झोंपड़ियों में खाने और म्यूजिक का मजा लें।

3) पाटन, गुजरात

गुजरात का पाटन घूमने के लिए एक सुंदर ऑफबीट डेस्टिनेशन है। पाटन पटोला साड़ियों के लिए काफी फेमस है, जो दुनिया के बेहतरीन हाथ से बने कपड़ों में से एक है।

4) ताडोबा, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र का यह शहर ताडोबा नेशनल पार्क ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व, ताडोबा झील, एराई बांध, मोहरली और खोसला गांव के लिए जाना जाता है। शहरों से दूर समय बिताने के लिए ये जगह सबसे अच्छी है। ताडोबा भारत में सबसे अच्छे टाइगर रिजर्व में से एक है और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा है। यहां सफ़ारी के लिए जाएं या जंगल में रह भी सकते हैं।

DETOX YOUR MIND

दिमाग में आते हैं उल्टे-सीधे ख्याल तो ऐसे करें माइंड को डिटॉक्स

लगातार काम के प्रेशर ने दिमाग को थका दिया है तो रोजाना की ये आदतें आपके माइंड को डिटॉक्स कर रिफ्रेश करने में मदद करेगी।



• जालंधर ब्रीज . फीचर

जिस तरह से उल्टी-सीखे खानपान से शरीर को बचाने के लिए बाँड़ी डिटॉक्स की जाती है। उसी तरह से माइंड को भी उल्टे-सीधे ख्याल से बचाने के लिए डिटॉक्स की जरूरत होती है। लगातार काम का प्रेशर, प्यूचर की टेंशन और तनाव माइंड को थका देता है। ऐसे में जरूरी है कि दिमाग को थोड़ा रिलैक्स किया जाए, जिससे कि माइंड रिफ्रेश हो। दिमाग को डिटॉक्स कर रिफ्रेश करना है तो कुछ खानपान बदलने की जरूरत नहीं लेकिन इन आदतों को जरूर शामिल करने की जरूरत है। जानें कैसे करें माइंड को डिटॉक्स।

ऐसे करें माइंड को क्लियर
दिमाग में आ रहे ख्याल और विचारों को क्लियर करना है तो सबसे पहले उन्हें लिखना शुरू कर दें। ऐसा करने से आप समझ जाएंगे कि दिमाग में चल रही कितनी बात काम की है और कितनी बात गैर जरूरी है। रोजाना ऐसा करने से कुछ दिनों में खुद ब खुद अंतर दिखेगा और माइंड ज्यादा क्लियर सोचना शुरू कर देगा।

अपना पसंदीदा काम करें
काम के प्रेशर और तनाव के बावजूद खुद के लिए समय निकालकर ऐसी जगह जाएं जहां जाना आपको खुशी देता है। गार्डन, पार्क, समंदर किनारे बीच या फिर आपका प्यारा बेंडरूम। वहां बैठकर थोड़ी देर रिलैक्स हों और वो काम करें जिससे खुशी मिलती हो।

रोजाना काम की लिस्ट बहुत लंबी होती है लेकिन तय करें कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में, ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा हड़बड़ी और दिमाग पर प्रेशर डालने की जरूर नहीं पड़ेगी।



डिस्क्लेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

कटिंग बोर्ड से आ रही बदबू से इस तरह पाएं छुटकारा, गंदगी भी होगी साफ

कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल सब्जियों की फाइन चॉपिंग करने में आता है। कुछ घरों में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गंदी बदबू आने लगती है। इस बंदबू और गंदगी साफ करने के लिए यहां बताए तरीकों को अपनाएं।



• जालंधर ब्रीज. रसिपी

किचन में कुछ चीजों का इस्तेमाल रोजाना किया जाता है। चकला, बेलन, तवा से लेकर रोजाना के बर्तन तक। इस चीजों में कटिंग बोर्ड भी शामिल है। सब्जियों की अच्छी चॉपिंग के लिए कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर लोग प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन की फाइन चॉपिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कटिंग बोर्ड पर प्याज की स्मेल आने लगती है। पानी और डिटर्जेंट के खूब इस्तेमाल के बाद भी इस बदबू से निपटना मुश्किल होता है। ऐसे में कुछ तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं।

पहला तरीका
इस बदबू से निपटने के लिए सबसे पहले कटिंग बोर्ड पर बेकिंग सोडा छिड़कें। फिर आधा कटा नींबू लें और इस नींबू से कटिंग बोर्ड को रगड़ना शुरू करें। अच्छे से रगड़ने के बाद साड़ा और नींबू को कुछ देर के लिए बोर्ड पर ही रहने दें। कम से कम 15 मिनट बाद ही कटिंग बोर्ड को पानी से धोएं।

दूसरा तरीका
इस तरीके में नींबू के साथ नमक का इस्तेमाल करें। हालांकि नमक के साथ रगड़ना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जब आप कटिंग बोर्ड पर नमक छिड़कें तब नींबू का रस भी साथ में डाल दें। फिर अच्छे से नींबू से रगड़ें।

कटिंग बोर्ड की बदबू से कैसे निपटें

तीसरा तरीका
कटिंग बोर्ड की गंदी बदबू से निपटने के लिए आलू या फिर सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए दोनों में से किसी एक चीज को कद्दूकस करें और फिर इसे बोर्ड पर कुछ देर के लिए रखने दें। बाद में इसे पानी से साफ करें।

टिप
कटिंग बोर्ड की गंदी बदबू से निपटने के लिए एक बाद ध्यान रखें कि जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करें वैसे ही इसे धो दें।

सनसेट एंजाइटी के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय

अगर सूरज ढलते ही आपको चिंता, तनाव और घबराहट महसूस होने लगती है तो, हो सकता है आप सनसेट एंजाइटी के शिकार हैं। यह समस्या उन लोगों में ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जो पहले से ही अपने रोजमर्रा के जीवन में स्ट्रेस और...

• जालंधर ब्रीज. हेल्थ केयर

अगर सूरज डूबते ही आपका मन भी उदास होने लगता है, आपको जीवन में खालीपन महसूस होने के साथ अनजाना डर सताने लगता है, जिससे आप खुद को तनाव में महसूस करते हैं तो हो सकता है आप सनसेट एंजाइटी के शिकार हैं। सनसेट एंजाइटी ज्यादातर उन लोगों को अपना शिकार बनाती है, जो पहले से ही अपने जीवन में किसी तरह के स्ट्रेस या प्रेशर को झेल रहे होते हैं। बता दें, सनसेट एंजाइटी एक तरह की मानसिक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति शाम के समय जरूरत से ज्यादा चिंता और स्ट्रेस फील करने लगता है। इस स्थिति में व्यक्ति को बहुत ज्यादा तनाव, डर या अनजाने भविष्य की चिंता सताने लगती है।

सनसेट एंजाइटी के लक्षण

- रात को सोने में मुश्किल हो सकती है।
- अकेलापन और खालीपन महसूस होना।
- सूर्यास्त के समय मन में उदासी और निगेटिविटी का आना।
- दिल की धड़कन तेज हो सकती है।
- शाम होते ही चिंता और बेचैनी का बढ़ जाना।
- पसीना आना।



- हाथ-पैरों में कंपन महसूस हो सकती है
- सांस फूलना।
- जरूरत से ज्यादा सोचना
- आत्मविश्वास की कमी हो सकती है।

सनसेट एंजाइटी के कारण

- डेली रूटीन सही नहीं होने से सनसेट एंजाइटी होती है।
- जिम्मेदारियों का दबाव
- पहले से अवसाद का होना
- जीवन में हुई कोई बुरी घटना
- जीवन का उद्देश्यहीन होना

सनसेट एंजाइटी से बचाव के उपाय

- सोने और उठने का एक समय।
- डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके तनाव और चिंता को कम करने की कोशिश करें।

आपका प्यार कहीं बन न जाए बच्चे की तरक्की में फंदा, समय रहते उठाएं सही कदम

• जालंधर ब्रीज . फीचर

इन दिनों ऐसी खबरों की भरमार है, जिनमें बड़े-बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे जीवन के छोटे-मोटे संघर्ष के आगे हार जाते हैं। वे व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में अपने जीवन और रिश्ते में सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए माता-पिता का सुरक्षात्मक घेरा तो जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक ही, ताकि व्यक्ति को बचपन में खुद की गलतियों से सीखने का अवसर भी मिल सके।

आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास में कमी - डॉ. ज्योति कपूर बताती हैं, 'माता-पिता के अति-सुरक्षात्मक घेरे से बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में जबरदस्त कमी आ जाती है। दुनिया का सामना करने के लिए हर व्यक्ति अपने हुनर का इस्तेमाल करता है। अति-सुरक्षात्मक घेरा यह हुनर विकसित नहीं होने देता है।' इसके कारण व्यक्ति में लचीलेपन और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है।

उग्र व्यवहार और अवसाद के शिकार - ऐसे बच्चे बड़े होने पर बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं। उनसे यदि कोई काम नहीं हो पाता है, तो उन्हें अवसाद होने लगता है। वे या तो उग्र व्यवहार करने लगते हैं या फिर उदासीन हो जाते हैं।

असुरक्षा का भाव - इस तरह के बच्चों में ना सुनने की आदत विकसित नहीं हो पाती है। इससे उन्हें बहुत अधिक असुरक्षा का भाव होता है। वे ऐसा चाहते हैं कि दूसरे लोग हमेशा उन्हें पसंद करें।

हमेशा दबाव में रहना - अत्यधिक सुरक्षात्मक माता-पिता के बच्चे अपने पूरे जीवन में दबाव में रहते हैं। बड़े होने पर वे डरपोक, निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति बन जाते हैं।

कैसे सुधारें अपना तरीका - पहले कदम से लेकर पहला स्कूल ड्रास तक, आपका बच्चा जीवन में ढेर सारी नई चीजें आजमाएगा। आपको उन्हें कुछ नया और रोमांचक करने के इन पहले अवसरों से डराना नहीं चाहिए। सुरक्षा का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन अपने मन से डर को निकाल दें और बच्चे को नई-नई चीजें और अनुभव आजमाने दें।

उनसे रोजमर्रा के काम की अपेक्षा करना जरूरी है। अपने बच्चे के साथ कुछ उचित नियम और सीमाएं निर्धारित जरूर करें।

डिस्क्लेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।



Parenting

नोट : इस खबर में बताए गए सुझाव सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। इसलिए किसी भी उपचार/दवा/डाइट को अपनाने से पहले डाक्टर या संबंधित एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

सशक्तता के बीज : आगामी बजट में भारतीय कृषि सुधार पर जोर

भारतीय कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18 प्रतिशत का योगदान देता है और लगभग 58 प्रतिशत आबादी को आजीविका प्रदान करता है। यह अनिवार्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और कई संबद्ध उद्योगों का समर्थन करता है। जैसे-जैसे हम वित्त वर्ष 2025–26 के लिए केंद्रीय बजट के करीब पहुंच रहे हैं, हमें उन असंख्य चुनौतियों को पहचानना चाहिए, जो इसकी स्थिरता और प्रगति को खतरों में डालती हैं। पिछले कुछ समय में, कर्मोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव और किसानों का बढ़ता कर्ज फिलहाल कृषि उत्पादकता और कल्याण पर विपरीत प्रभाव डालता है। मध्यम अवधि की चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए स्थायी प्रणालियों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता शामिल है, ताकि पारंपरिक कृषि पद्धतियां बाधित न हों। भविष्य का ध्यान रखते हुए, इस क्षेत्र को तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए नवाचार को अपनाना और विकास की ओर बढ़ना चाहिए। नीति निर्माताओं को आगामी बजट में दीर्घकालिक सतत विकास पहलों के साथ इन तत्काल दबावों को रणनीतिक रूप से संतुलित करना चाहिए। संकटग्रस्त किसानों के लिए तत्काल राहत के उपायों को प्राथमिकता देकर, जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों में निवेश करके और नवाचार को बढ़ावा देकर, सरकार कृषि क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बना सकती है, जो आर्थिक विकास का समर्थन करे और भारतीय कृषि के भविष्य को सुरक्षित करे।

कृषि अनुसंधान एवं विकास में ऊंची छलांग – समय की आवश्यकता – भारतीय कृषि अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को बहुत कम धन उपलब्ध है, जो वैश्विक औसत 1 प्रतिशत की तुलना में कृषि सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.4 प्रतिशत है। यह कम नवाचार और जलवायु-अनुकूल फसलों, जल प्रबंधन और उन्नत कीट नियंत्रण जैसी

महत्वपूर्ण चुनौतियों के लिए समाधान अपनाने में बाधा डालती है। बजट में आरएंडडी आवंटन को दोगुना करना चाहिए, आईसीएआर और एसएयू जैसे संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से प्राप्त बेहतर कर लाभों के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये पहल शिक्षाविदों, उद्योग और किसानों के बीच मजबूत सहयोग पर आधारित इको-सिस्टम का निर्माण करेगी, जिससे ऐसी सफलताएं सुनिश्चित होंगी और कृषि उत्पादकता के साथ-साथ स्थायित्व को बढ़ावा मिल सकता है।

फसल की कटाई के बाद के नुकसान को कम करने हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी दूर करना – भारत में फसल की कटाई के बाद का नुकसान सालाना 10–20 प्रतिशत तक होता है, जो भंडारण, रसद और वितरण संबंधी अक्षमताओं को चिह्नित करता है। कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर कोष के अंतर्गत आवंटन से बावजूद, ये अंतर अपनी जगह कायम हैं। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधा, कोल्ड चेन और डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि बर्बादी को कम किया जा सके और किसानों का बाजार से संपर्क बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, बढ़ते खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और बढ़ती प्रति व्यक्ति आय भारत में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग को बढ़ाती है। इसके लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है। मशरूम की खेती और मधुमक्खी पालन जैसी वैकल्पिक कृषि गतिविधियों में निवेश करने से अतिरिक्त ग्रामीण रोजगार पैदा हो सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई पहलों का विस्तार करने से उत्पादकता में और भी अधिक वृद्धि होने के साथ ही पानी की कमी दूर की जा सकेगी।

जलवायु अनुकूलन : कृषि नीति का एक नया स्तंभ – अप्रत्याशित मौसम, बेमौसम बारिश और मिट्टी के क्षरण के कारण जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि के लिए जोखिम उत्पन्न

करता है। फसल विविधीकरण और प्राकृतिक तथा जैविक खेती सहित टिकाऊ प्रणालियों के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता आवश्यक है। जल की कमी वाले क्षेत्रों को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का विस्तार करना और सौर ऊर्जा से सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान करना जलवायु के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद कर



सकता है। तिलहन और दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए लक्षित मिशन-मोड कार्यक्रम जलवायु से जुड़ी चुनौतियों से निपट सकते हैं, साथ ही आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं।

फसल विविधीकरण : किसानों की आर्थिक मजबूती का माध्यम – पशुधन, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे संबद्ध क्षेत्रों में आय स्रोतों में विविधता लाना किसानों की फसल आय पर निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक है। पशुधन कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 28 प्रतिशत है, और मत्स्य पालन को पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि और पीएमएमएसवाई जैसी लक्षित योजनाओं के माध्यम से अधिक धन की आवश्यकता है। इसी तरह, बागवानी इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश, जैसे कि फ्रीजिंग, भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़ी सुविधाएं, इस क्षेत्र की निर्यात क्षमता को बढ़ा सकती हैं। बजट में इन क्षेत्रों को एक ऐसी समेकित कृषि प्रणाली में एकीकृत किया जाना चाहिए, जो किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करे।

डिजिटल कृषि : खेती की परंपराओं में

सुधार = कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रिया-कलाप शामिल होने से निर्णय प्रक्रिया और दक्षता में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। पारदर्शिता और बाजार की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ई-एनएएम जैसे प्लेटफॉर्म का विस्तार करके इसमें सभी मॉडियों को शामिल किया जाना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, फसल बीमा और मृदा स्वास्थ्य निगरानी में एआई और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों को एक साथ जोड़ने से दक्षता और जोखिम प्रबंधन में काफी सुधार हो सकता है। 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना के लिए मजबूत वित्तीय और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, ताकि सामूहिक सौदेबाजी और बाजार पहुंच में वृद्धि के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को सशक्त बनाया जा सके।

डिजिटल इकोसिस्टम के साथ स्मॉट और वायदा बाजारों को जोड़ना – केंद्रीय बजट में मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम और डेटा-संचालित संरचना विकसित करके स्मॉट और वायदा बाजारों को एक साथ जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ई-एनएएम जैसे डिजिटल स्मॉट बाजारों का विस्तार करके इसमें सभी मॉडियों को शामिल करना और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसीट (ई-डब्ल्यूआर) से जोड़ना किसानों को उनकी फसल की कुल उपज का मुद्रीकरण करने, संकट की स्थिति में बिक्री को कम करने और वैश्विक व्यापार मानकों का अनुपालन करने में सक्षम बना सकता है। वस्तुओं के लिए एक केंद्रीकृत डेटा भंडार, वेयरहाउसिंग सिस्टम, ट्रैडिंग प्लेटफॉर्म और सरकारी एजेंसियों से इनपुट को समेकित करके, वायदा बाजारों में सटीक मूल्य का पता लगाने और जागरूक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, स्मॉट और वायदा बाजारों के विकास को सुसंगत बनाने के लिए लगातार नीतिगत समर्थन आवश्यक है। इस पूरी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे इनके बीच तालमेल बिठाते हुए कार्य करें। यह दृष्टिकोण पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, मूल्य

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे : विकसित भारत के लिए महिला नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने का सफर जारी

जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के अपनी मंज़िल की तरफ आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का परिवर्तनकारी प्रभाव इस बात का प्रमाण है, कि हम महिलाओं के विकास से महिला-नेतृत्व में विकासतक के सफर में कितने आगे आ गए हैं। स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था, "जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। किसी भी पंछी के लिए महज एक पंख के साथ उड़ना संभव नहीं है।" उनके इस कालजयी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीपीओ) योजना की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक पहल का मकसद भारत में गिरते बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) पर ध्यान देना और यह सुनिश्चित करना था कि देश भर में लड़कियां और महिलाओं को वे सभी अवसर, देखभाल और सम्मान मिलें, जिनकी वे हकदार हैं।

2011 की जनगणना में बाल लिंग अनुपात 918 होने के साथ सामाजिक पूर्वाग्रहों और नैदानिक उपकरणों के दुरुपयोग की चिंताजनक तस्वीर सामने आई। एक लक्ष्य के साथ तथा जीवन-चक्र-केंद्रित कदमों के ज़रिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को न केवल इस तस्वीर को बदलने के लिए लॉन्च किया गया था, बल्कि एक ऐसे भविष्य की नींव भी रखी गई, जहां महिलाएं नेतृत्व करें और आगे बढ़ें।

पिछले एक दशक में, इस योजना ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार, 2014–15 में जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात 918 से बढ़कर 2023–24 में 930 हो गया है। संस्थागत प्रसव के मामले भी 2014–15 में 61% से बढ़कर 2023–24 में 97.3% हो गए हैं, जबकि पहली तिमाही में प्रसवपूर्व देखभाल पंजीकरण 61% से बढ़कर 80.5% हो गया है। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014–15 में 75.51% से बढ़कर 2021–22 में 79.4% हो गया। इसके अलावा, पुरुष और स्त्री नवजात शिशुओं के बीच शिशु मृत्यु दर में अंतर तकरीबन खत्म हो गया है, जो उन्नतजीवित और देखभाल में समानता के

प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, आंकड़ों में सुधार की सीमा से कहीं आगे निकल गया है।इसने महिला सशक्तिकरण के मायने ही बदलकर रख दिए हैं। अक्टूबर 2023 में 150 महिला बाइकर्स द्वारा 10,000 किलोमीटर की यात्रा, यशस्विनी बाइक अभियान जैसी पहल, भारत की बेटियों के अदम्य साहस का प्रतीक है। 2022 में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ने, स्कूल न जाने वाली करीब 1,00,786 लड़कियों को फिर से स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया, जो जीवन को बदलने में शिक्षा की शक्ति का प्रदर्शन है। कौशल विकास पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन ने, कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया, जिससे हम महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के अपने दृष्टिकोण के और करीब आ पाए।

आज, जब हम इस परिवर्तनकारी पहल के दस साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, साफ है कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें अगर विकसित भारत के अपने सपने को हासिल करना है, तो यह तय करना जरूरी है कि लड़कियाँ और महिलाएं हमारे राष्ट्र-निर्माण प्रयासों के केंद्र में रहें। भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता, जब तक इस देश की लड़कियाँ और महिलाएँ अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के काबिल नहीं हो जातीं। यह हमारे लिए निर्णायक कार्रवाई करने का वक़्त है। हमें गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम 1994 के कार्यान्वयन को मजबूत करना चाहिए, शिक्षा में ड्राइपआउट दर को संबोधित करना चाहिए, कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए और लड़कियों के जीवन के हर चरण में ज़रूरी मदद देनी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए, भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 41.7% थी। हालाँकि यह पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, लेकिन फिर भी यह पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी के मुकाबले कम है। गौर करने की बात यह भी है कि शहरी क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी से कम है।

के वैश्विक प्रभाव को मान्यता देते हुए वर्ष 2025 को "अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष" घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरक दृष्टि और रणनीतिक नेतृत्व ने भारत के सहकारी आंदोलन को वैश्विक महत्व दिया है। ज़मीनी स्तर पर सशक्तिकरण पर उनके जोर के साथ-साथ अमिट शाह जी की सहकारी मॉडल की गहरी समझ ने इस क्षेत्र को दुनिया के लिए आशा की नई किरण के तौर पर पेश किया है। इस सम्मेलन की सफलता उनके अनुकरणीय नेतृत्व और वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है।

कई अंतर्राष्ट्रीय सहकारी नेताओं ने भारत के सहकारी आंदोलन के बारे में जानने और भारत में प्रमुख सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी की खोज करने में गहरी रुचि व्यक्त की। इस अनुभव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (दुनिया एक परिवार है) के दृष्टिकोण की भावना को मजबूत किया, जो हमारे राष्ट्र के मूल्यों और परंपराओं से मेल खाती है। भारत को डेयरी सहकारी समितियां 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के दृष्टिकोण और सहकारिता की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से खड़ी हैं। अमूल डेयरी कोऑपरेटिव की स्वप्निल यात्रा विस्मय करके यह दुनिया को सबसे बड़ी डेयरी सहकारी समितियों में से एक बन गई है। इसके अलावा, "आणंद पैरन" पर आधारित अमूल की सफलता, जिसमें किसान हो सह-स्वामी होने के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता भी हैं, ने आय और लाभ का उचित वितरण के लिए एक मंच प्रदान करती है जो इसे देश और दुनिया भर की अन्य कृषि और डेयरी सहकारी समितियों के लिए एक आदर्श खंका बनाती है। इस चरण के लिए कायम करने से सहकारिता के आदर्शों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई है। मैंने 30 साल पहले 1995 में 'वसुधरा-अमरेली' नामक संगठन की स्थापना की थी। यह संगठन वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धांत को बढ़ावा देने के महान लक्ष्य से प्रेरित है। इसका उद्देश्य सभी जीवित प्राणियों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देना है।

का पता लगाने की संभावना बढ़ाएगा और एक कृषि बाजार के एक मजबूत इको-सिसस्टम का निर्माण करेगा, जो वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देते हुए सभी हितधारकों को सशक्त बनाएगा।

लघु और सीमांत किसानों की ऋण तक पहुंच बढ़ाना – संस्थागत ऋण तक पहुंच छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, जिसमें किरायेदार किसान भी शामिल हैं, जिनकी संख्या भारत के शहरीकरण के साथ बढ़ रही है। ये किसान अक्सर अनौपचारिक ऋणदाताओं से उच्च ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं। छोटे और पट्टे पर खेती करने वाले किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को 20 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपये करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से फसल बीमा अपनाने को बढ़ावा मिल सकता है। एक मजबूत ऋण और बीमा संरचना किसानों की सुरक्षा कर सकता है, उनकी वित्तीय कमजोरियां कम कर सकता है और लाभदायक निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है।

महिला सशक्तीकरण : भारतीय कृषि का आधार – भारत के कृषि कार्यबल में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। उन्हें संसाधनों तक पहुंचने और निर्णय लेने वाले प्लेटफार्मों में भाग लेने के लिए प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे लगभग 33 प्रतिशत कृषि भूमि मालिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं, किंतु उनके पास अस्सर और और परिसंपत्तियों में नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे में यह बात महत्वपूर्ण है कि उन्हें कौशल विकास, भूमि स्वामित्व अधिकार और संस्थागत ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देने हेतु महिला-पुरुष आधारित विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए जाएं। बजट में महिला किसानों को सशक्त बनाने की पहल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने में उनकी आवश्यक भूमिका को स्वीकार

पश्चिमी कमान ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की उभरती भूमिका पर सेमिनार आयोजित किया



जालंधर ब्रीज (जालंधर) . पश्चिमी कमान ने चंडीमॉंदिर सैन्य स्टेशन में ‘भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की उभरती भूमिका और योगदान’ पर सेमिनार आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार,जीओसी-इन-सी पश्चिमी कमान ने की।

सेमिनार में महिला अधिकारियों को सेना में आने वाली चुनौतियों, जिसमें कार्य-जीवन संतुलन, कैरियर की प्रगति और नेतृत्व शैली जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में मेंटरशिप कार्यक्रमों को बढ़ाने, तैनाती नीतियों की समीक्षा करने और महिला अधिकारियों और सैनिकों की सहायता के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने नेतृत्व प्रशिक्षण, लैंगिक संवेदनशीलता कार्यशालाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से भर्ती अभियान जैसी पहलों का हवाला देते हुए लैंगिक समावेशिता के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सेना कमांडर ने अपनी कमान को संवारने और आकांक्षाओं और कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में कर्माडिंग अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कमान में महिला अधिकारियों की जड़बे और उत्साह पर संतोष व्यक्त किया, जो अपने पुरुष समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं। सेमिनार का समापन लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने भारतीय सेना को एक बेहतर संगठन बनाने के लिए महिला अधिकारियों को शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से सतर्क और साफ नैतिकता होने के महत्व पर जोर देने के साथ हुआ।



सहकारिता रूपी नदी धाराप्रवाह बहती जा रही है। यह किसी बंधन से नहीं बांधी जा सकती है। यह जहां भी जाती है, विकास के छोटे से लेकर बड़े बीज बोती जाती है और आर्थिक समर्थन का आधार पैदा करती है। वास्तव में, इसके शाब्दिक अर्थ से ये कहीं अधिक, सहकारिता सामाजिक और आर्थिक उत्थान का द्योतक है। हम सभी किसी न किसी तरह सहकारिता से जुड़े हुए हैं, और इसकी यात्रा में निरंतर सहयोग कर रहे हैं।

भारत की सहकारी परंपरा प्राचीन है, जिसकी जड़ें इसकी संस्कृति और आर्थिक प्रणालियों में गहरी पैठ रखे हुए है। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, गाँवों की वित्तीय संरचना सहकारी ढाँचे, रोजगार प्रदान करने, परिवारों का समर्थन करने और सामाजिक विकास में योगदान करने को दर्शाती हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी सहकारिता की भावना की प्रमुख भूमिका थी। रियासतों को एकटूट करने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल के दूरदर्शी प्रयासों और महात्मा गांधी के ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन ने सामाजिक सहयोग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार, यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि

सहकारिता हमारे राष्ट्र के लोकाचार में शुरू से ही शामिल रही है। सहकारी मॉडल की परिवर्तनकारी क्षमता पहचानते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की, जो आधुनिक भारत में एक ऐतिहासिक कदम है। यह पहल समावेशी विकास और समृद्धि के लिए मोदी जी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, जो एक अनुभवी सहकारी नेता हैं, ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शी नीतियों और मार्गदर्शन में भारत के सहकारी आंदोलन को एक नई दिशा मिली है, जिसमें "सहकार से समृद्धि" के सूत्र वाक्य पर जोर है। अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हो रहा है और वैश्विक स्तर पर यह क्षेत्र तेजी से मान्यता प्राप्त कर रहा है।

लगभग 132 साल पहले स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने नवंबर 2024 में 107 से अधिक देशों के साथ

भारत में अपनी पहली बैठक की। भारत के सहकारी इकोसिस्टम की बढ़ती ताकत को देखना सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल था। नई दिल्ली में इफको द्वारा आयोजित आई. सी. ए. वैश्विक सम्मेलन की सफल



मेजबानी से भारत ने सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आई. सी. ए. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया, जिसमें भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोयगो, फिजी के उप-प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका, आई. सी. ए. के अध्यक्ष एरियल ग्वार्को और 107 देशों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान, संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता क्षेत्र

के लिए मजबूती से खड़ी हैं। अमूल डेयरी कोऑपरेटिव की स्वप्निल यात्रा विस्मय करके यह दुनिया को सबसे बड़ी डेयरी सहकारी समितियों में से एक बन गई है। इसके अलावा, "आणंद पैरन" पर आधारित अमूल की सफलता, जिसमें किसान हो सह-स्वामी होने के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता भी हैं, ने आय और लाभ का उचित वितरण के लिए एक मंच प्रदान करती है जो इसे देश और दुनिया भर की अन्य कृषि और डेयरी सहकारी समितियों के लिए एक आदर्श खंका बनाती है। इस चरण के लिए कायम करने से सहकारिता के आदर्शों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई है। मैंने 30 साल पहले 1995 में 'वसुधरा-अमरेली' नामक संगठन की स्थापना की थी। यह संगठन वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धांत को बढ़ावा देने के महान लक्ष्य से प्रेरित है। इसका उद्देश्य सभी जीवित प्राणियों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देना है।

करना चाहिए।

भारत को कृषि व्यापार में वैश्विक अग्रणी बनाना – भारत के कृषि निर्यात में वृद्धि की अपार संभावना है, जिसका मूल्य 2023–24 के लिए 50 बिलियन डॉलर है। निर्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर और रसद को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित करने से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। जैविक और मूल्यवर्धित उत्पादों में निवेश कर मूल्य वाले अंतरराष्ट्रीय बाजारों को लक्षित कर सकता है। रणनीतिक व्यापार साझेदारी और द्विपक्षीय समझौतों में गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और भारतीय निर्यात को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। किसान प्रतिनिधियों और व्यापार विशेषज्ञों से युक्त एक वैधानिक निकाय व्यापक निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकता है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए देश के किसानों के हितों को रक्षा करे।

संक्षेप में, केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2025–26 भारतीय कृषि के भविष्य की फिर से कल्पना करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके तथा अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देने, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने, जलवायु के प्रति अनुकूलन को बढ़ावा देने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने जैसी रणनीतिक पहलों को लागू करके, सरकार कृषि को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप में आगे बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्रगति के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना और ऋण तक समान पहुंच सुनिश्चित करना अर्थव्यवस्था के आधार को मजबूत करेगा और लाखों लोगों के लिए स्थायी आजीविका प्रदान करेगा। जीएसटी परिपक्व की तर्ज पर कृषि विकास परिपक्व (एडीसी) की स्थापना वर्तमान समय की मांग है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषि विकास और नवाचार का एक शक्तिशाली प्रतीक बनकर दूसरों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित कर सकती है।

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.